

(1400/PC/SAN)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I had requested you for allowing me tomorrow to raise the issue of speedy completion of Pithapuram-Kakinada main railway line, but I have got the opportunity today. This is my maiden speech, Mr. Speaker, Sir, and I thank you so much.

On behalf of the people of my parliamentary constituency, the well-wishers and the main agitators of completion of Kakinada-Pithapuram main railway line, I am raising this issue. This has been continuing for 30 to 40 years, but the project has not been completed till now. Every year, some money is allocated for Pithapuram-Kakinada main railway line, but the Railway Department is not taking any action to complete that line. So, Sir, I request, through you, the Railway Minister and the Central Government for speedy completion of Pithapuram-Kakinada main railway line for the benefit of the people and for the development of Kakinada parliamentary constituency.

Thank you.

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Respected Speaker Sir, first of all, I thank you for giving me an opportunity to speak in the 'Zero Hour'.

मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गिरणा रिवर है, उस पर एक बैराज - गिरणा डैम है। 40 सालों में सिर्फ सात बार वह डैम आज तक अपनी कैपैसिटी तक फिल-अप हुआ है। 33 वर्षों में वहां कोई रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं लिया गया, इसलिए वहां पानी नहीं आ सकता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लगातार इरिगेशन मिनिस्ट्री से मांग चल रही है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मिनिस्ट्री को यह सुझाव दिया जाए कि जो नार पार गिरना प्रोजेक्ट है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए तथा एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. भारती प्रवीण पवार एवं डॉ. हिना विजयकुमार गावीत को श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तपन कुमार गगोई (जोरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं असम के जोरहाट से हूँ। असम की छः कम्युनिटीज -अहोम, कोच-राजबोंगशी, मोरन, मटक, चुटिया और टी-ट्राइब्स को एस.टी., अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं।

महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध कना चाहता हूँ कि इन छः कम्युनिटीज को जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की व्यवस्था की जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तपन कुमार गगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो हफ्तों से कर्नाटक की राजधानी कुछ गलत विषय के लिए चर्चा में है। मंसूर अली खान नाम के एक व्यक्ति ने आईएमए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बनाकर लगभग 50 हजार गरीब लोगों को धोखा दिया। निवेशकों को ज़्यादा ब्याज देने का लालच दिया गया था। वह दो महीनों से लापता है। इसी घोटाले में 15 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हुआ है। अभी तक 40 हजार मामले बेंगलुरु और अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में दर्ज हुए हैं।

अध्यक्ष जी, ये निवेशक बहुत गरीब लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्जियां बेचने वाले और मज़दूरी कर के घर चलाने वाले हैं। उन्होंने आईएमए में पैसा रखा था, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, किसी ने नया घर बनाने के लिए रखे थे, किसी ने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखे थे। अब उनके पास जमापूजी के रूप में सिर्फ आंसू बाकी हैं।

सर, यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सरकार शामिल है। आईएमए के मालिक मंसूर अली खान के रिश्ते कांग्रेस और जेडी (एस) नेताओं के साथ भी हैं। इसी धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक के जेडी (एस) के एक मंत्री, कांग्रेस के विधायक, राज्य के बहुत सारे नेता एवं बहुत सारे अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ...(व्यवधान) कल मंसूर अली खान ने दुबई में बैठकर एक वीडियो क्लिप जारी कर इस घोटाले में बड़े-बड़े व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है। ...(व्यवधान) आईएमए के एमडी मंसूर अली खान का रिश्ता आतंकवादियों के साथ भी है। ...(व्यवधान) कर्नाटक सरकार

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

...(व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): सर, मुझे एक मिनट और दीजिए। ...(व्यवधान) कर्नाटक सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बैठाई है, मगर निवेशक और कर्नाटक की जनता एसआईटी पर विश्वास नहीं कर रही है। ...(व्यवधान) स्वयं राज्य सरकार इस घोटाले में शामिल है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

...(व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): सर, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस मामले को जल्दी दबा देगी। ...(व्यवधान) ऐसा पहले भी हुआ था। ...(व्यवधान) कर्नाटक राज्य सरकार ने बहुत केसेज़ को दबा दिया था। ...(व्यवधान) इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की सीबीआई और इनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से जांच करवाई जाए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1405/SM/SPS)

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee.

... (*Interruptions*)

1405 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I am really very grateful to you for giving me a chance...(*Interruptions*) I feel I am lucky that I am going to raise this issue, when the Hon. Railway Minister is also present here.

Sir, my issue is about the setting up of a railway line from Furfura Sharif to Dankuni. In 2010, the then hon. Railway Minister, Ms. Mamata Banerjee started this project. But from 2014, it has been stopped totally. In Furfura Sharif, there is a mosque built by Muqlish Khan in 1375 as a site for Muslim pilgrimage, especially during the [Pir's](#) mela (fair). It attracts lakhs and lakhs of pilgrims during the Urs festival. Furfura Sharif contains the [mazaar](#) of one Abu Bakr Siddique and his five sons, popularly known as the *Panch Huzur Keblah*. He was a social and religious reformer.

Sir, what I am urging and praying is that this scheme is already announced. It has been commenced by the Railways. So far as my knowledge goes, it was giving at least 20 to 25 per cent employment also because the lands were taken. Now, the project from Furfura Sharif to Dankuni should be completed.

It is my humble request, through you, to the hon. Railway Minister and I feel that because of the grace of God, the Railway Minister is also present here.

Earlier also, he considered so many requests of mine. This is my first request to him in the 17th Lok Sabha.

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COAL (SHRI PIYUSH GOYAL): I am his friend also.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Yes Sir. But first I have to refer to you as the hon. Minister.

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। छत्रपति शाहू महाराज की जयन्ती के अवसर पर मैं उनकी पावन स्मृति का विनम्र अभिवादन करती हूँ। मैं आपके माध्यम से आज देश में घट रही रैगिंग की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आज कई व्यावसायिक कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले मुम्बई के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पायल तड़वी नाम की एक डॉक्टर के साथ भी इसी प्रकार की रैगिंग की घटना घटी। रैगिंग से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करती हूँ कि इस केस की निष्पक्ष इन्क्वायरी हो और डॉक्टर पायल तड़वी को न्याय मिले। इसी के साथ मैं सरकार से मांग करती हूँ कि एण्टी रैगिंग लॉज को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि देश में कोई दूसरी डॉक्टर पायल तड़वी न बने।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। आपने आज नए सदस्यों को बोलने का जो विशेष अवसर दिया है, यह सचमुच एक अच्छी परंपरा है, जिसकी शुरुआत आपने की है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पिछले कार्यकाल में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देशी हवाई उड़ान सेवाएं शुरू करने का एक कार्यक्रम जारी किया था। उसमें कुछ हवाई अड्डों का चयन हुआ था। मेरे सतना लोक सभा क्षेत्र में भी उस हवाई

अड्डे का चयन हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह कहा था कि उन हवाई अड्डों को परिचालन योग्य बनाने के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए, उनका विस्तारीकरण करने के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक एक पैसा नहीं मिला।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सतना से हवाई परिचालन शुरू किया जाए, हवाई अड्डे के रिनोवेशन के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। उसका जो एरिया है, वह लगभग 1850 मीटर है। इसकी 200 मीटर लम्बाई बढ़ाना जरूरी है। एक प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। मैं उसकी मंजूरी चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1410/KDS/SPR)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): अध्यक्ष जी, मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आपने सभी नए सांसदों को बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के बीहटा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के नामकरण के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी, जो किसान नेता रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, उन्होंने एक संत के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए लगा दिया। वह लगातार किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वह उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, मगर उनका कार्यक्षेत्र बिहार था। खासतौर पर वर्ष 1927 में वह समस्तीपुर जिले से हमारे संसदीय क्षेत्र बीहटा में आए थे और बीहटा में उनका स्थायी निवास हो गया था। बीहटा में सीताराम दास द्वारा प्रदत्त भूमि को उन्होंने अपना स्थाई निवास बनाया था। वह लगातार किसानों के लिए काम करते रहे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पुरखों के नाम पर संस्थानों का नाम रखने का काम किया है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पटना में एक एयरपोर्ट है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अलग से एक एयरपोर्ट खोलने का काम किया है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह अभी निर्माणाधीन है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसका कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए। राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, जमीन का आवंटन भी कर दिया है, चारदीवारी भी हो गयी है, मगर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मगर यह प्रस्तावित है। सरकार ने उसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया है।

सर, जब यह एयरपोर्ट बनेगा तो उसका नाम स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी के नाम से हो, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। यह लोगों की जनभावना है और इसके लिए अभियान चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि पटना में बीहटा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट को स्वामी जी के नाम पर रखा जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। हमें आपका संरक्षण भी चाहिए। आप अपने स्तर से इसमें कुछ हस्तक्षेप भी करिए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I congratulate you on the way that you have forgotten your hunger pangs and you are sitting in your Chair to give chance to new and old Members. This is indeed an example for posterity as to how a Speaker should work.

I point out about another case of lynching of one Tabriz Ansari in Sarai Kalan, Jharkhand on the 22nd of June. This has already been mentioned in this House but what I want to mention is that the police held this man in custody for

four days. He had severe injuries on his head, and when he was brought to the hospital, he was already half dead. It was a coldblooded murder by a religiously motivated mob. The death of the 24 year old man is a blot on humanity. The unfortunate thing is that this man was beaten up and made to say, *Jai Sri Ram, Jai Hanuman*, before he was removed.

All I want to say is, the BJP Members are speaking about West Bengal, you should rather protect the people in Jharkhand, a BJP ruled State, and other places where people are being lynched to death. This is not the first case. This is an example of religious intolerance. We shall continue to protest against all instances of religious intolerance and mob lynching.

माननीय अध्यक्ष: श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) Sir, I am indeed indebted to you for allowing me to raise this issue. It is an international issue also with national ramifications. President Trump's decision to pull back from airstrikes on Iran after an American Drone was shot down over the Strait of Hormuz was a rare moment of restraint amid escalating tensions between the two countries. The United States need to deescalate its maximum pressure tactics applied on Iran. Iran was fully compliant of the Nuclear Deal. Yet, the United States pulled out of the Deal which set off the escalation. The maximum pressure tactics as it is being quoted have led to tension between Iran and the United States.

(1415/UB/MM)

It is escalating day by day. Iran in response to the US pressure threatened to repeal the Nuclear Agreement that was intended to curb Tehran's ambition in exchange for relief from economic sanctions. But the US statement that it would stop extending sanction waiver to nations importing Iranian oil has direct impact on India as Tehran is the third largest oil supplier to India. Now, India has stopped importing oil from Iran which not only increases the cost of imported oil for India but also adversely affects India's bilateral relationship with Iran.

I, therefore, urge upon the Government to finely balance its approach towards Iran and the United States in defusing such tensions since a significant amount of Indian interests lie in both the countries. While Iran and the United States are on the edge of an abyss, India should play its diplomatic role behind closed doors to find a way out.

Today, the Secretary of State of the United States is in India and a discussion is also taking place in Delhi. Tonight, the hon. Prime Minister is leaving for Osaka in Japan and he will be meeting the President of Russia and also the Prime Minister of Japan. There is a need to have closed-door meetings so that the President of China, the President of Russia and the Prime Minister of India work together to defuse tensions in the Middle East and work out a profitable formula.

माननीय अध्यक्ष: श्री अनुभव मोहंती और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में मछुआरों की स्थिति पर बोलना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर्स का समुद्री तट है और मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्राम्बे कोलीवाड़ा, माहुल कोलीवाड़ा, शिवडी कोलीवाड़ा, माहिम कोलीवाड़ा और धारावी कोलीवाड़ा में मछुआरे रहते हैं। मछुआरों का पूरा जीवन समुद्र पर निर्भर करता है। पिछले कई सालों से मत्स्य व्यवसाय में उपयोग होने वाली सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत छोटी नाव खरीदने के लिए जो ऋण दिया जाता है उस पर 9 परसेंट से लेकर 15.25 परसेंट तक ब्याज लगाया जाता है, जो राष्ट्रीय बैंकों की ब्याज दर से भी ज्यादा है। अभी हमने मत्स्य व्यवसाय करने वालों को किसान का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से किसानों का ऋण माफ किया गया है, उसी प्रकार से मछुआरों का भी राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत दिए गए ऋण को माफ किया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, cashew industries are facing a serious crisis throughout the country. More than two-lakh cashew workers, about 90 per cent of them are poor women who are working in cashew industries, are affected. More than 400 cashew factories were closed due to various reasons. These poor cashew workers lost their employment because of the wrong policies of the Central and State Governments. The cashew workers are also not getting the benefits of ESI and PF properly. Wrong import policy of the Government of India on raw cashew nuts has seriously affected the cashew workers as well as the cashew factory owners. Even the Government of Kerala Undertaking, CAPEX, is also facing a serious crisis.

Hon. Speaker, nationalised banks are not releasing sufficient funds for running the cashew industries and are also not giving sufficient time to repay the loan.

Sir, I am requesting the Government of India through you to stop the import of raw cashew nuts from abroad. The Government of India has imposed a tax on raw cashew nuts. That is why, the cashew factory owners are not importing sufficient raw cashew nuts in this country.

(1420/KMR/SJN)

Sir, I would also request the Government, through you, to announce a revival package for the cashew industry. EPF and ESI benefits are also very important as far as cashew workers are concerned. The EPFO has recently taken a decision that to get pension benefits a worker should have 3,700 working days. That adversely affects the cashew workers. Therefore, I would request the Government, through you, to withdraw this decision of 3,700 working days limit. Thank you.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जालौर-सिरोही लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। जालौर-सिरोही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक पीछे है। सिरोही में हमारा केन्द्रीय विद्यालय माउंटआबू में बना हुआ है, लेकिन हम वहां बच्चों को भेजने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिरोही जिला और जालौर जिला धनुष के आकार में बना हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि हमें सिरोही में एक केन्द्रीय विद्यालय दिया जाए। जालौर जिले में जो सायला क्षेत्र है, वह धनुष आकार का होने के कारण वहां पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, तब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि आधारित डिस्ट्रिक्ट होने कारण के वहां के बच्चों

को पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिए केन्द्रीय विद्यालय और एक जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत जरूरत है। अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस हाउस का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि फॉरेस्ट फायर है। आज सरकार मैसिव ट्री प्लान्टेशन स्कीम पूरे देश में लागू कर रही है। मुझे लगता है कि यह आपके दिल के भी बहुत करीब है। मैंने पढ़ा है कि आपने भी अपने संसदीय क्षेत्र में एक लाख पौधे लगाने का काम किया है। नेशनल फॉरेस्ट पालिसी के उद्दिष्ट हमारे देश का 33 प्रतिशत भौगोलिक एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। महाराष्ट्र ने भी इस ओर पहल की है, जिसके तहत 4 करोड़, 13 करोड़ और 33 करोड़ पौधे गत तीन वर्षों में लगाने की मुहिम छेड़ दी गई है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, अगर उसको कंट्रोल करना है, तो हर एक इंसान को पौधे लगाना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है, आज जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हैं, वह 49 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं। यह फॉरेस्ट फायर सिर्फ नेशनल फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं है। मुंबई में जो अर्बन फॉरेस्ट है, उसके सराउन्डिंग सब अर्बन रीजन तक भी बढ़ गया है। 6,500 हेक्टेयर फॉरेस्ट अब तक जलकर खाक हो चुका है। उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। यह पता चला है कि जो 90 फीसदी फॉरेस्ट फायर है, वह direct or indirect result of human interface. मैंने भी एक मुहिम छेड़ी और वर्ष 2017-18 में लाखों पौधे लगाने की योजना बनाई। हमने वहां पर हजारों लोगों की मदद से मैन मेड फारेस्ट बनाने की इच्छा जाहिर की और पौधे लगाए। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि दो साल में, दोनों बार जंगल में आग लगाई गई और किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह एक यूनियन लेजिस्लेशन लेकर लाएँ और जो भी दोषी हों, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी फॉरेस्ट आफिसर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी नेग्लिजेन्स भी फिक्स हो और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हम जो पौधे हर साल लगाते हैं, उसका थर्ड पार्टी आडिट होना चाहिए, ताकि हर साल हम जितने पौधे

लगाते हैं, उनमें से अगले साल तक कितने पौधे जिंदा बचे, उसकी गणना की जा सके। उसके तहत यह जो ट्री प्लान्टेशन प्रोग्राम है, वह आगे जारी रहे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजानन कीर्तिकर को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Commerce and Industries Minister and my beloved friend Piyush Goyal Ji to the Sivakasi fireworks industry which for the past 100 years has gone through many struggles. Over the past four months, the whole industry is closed because of a Supreme Court order. PESO now has to submit a report to the Supreme Court and the standard of emission has to be fixed.

(1425/SNT/GG)

But, till date, due to the Central Government's policy, the PESO has not defined the emission limits. In October/November, *Deepawali* is going to be there. The industry is suffering. There are one million workers depending upon it. So, I would like to request the Minister to pay his attention to this issue.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके अध्यक्षपीठ पर आसीन होने के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका दूसरा अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूँगा कि आपने ज़ीरो ऑवर का उत्तर एक महीने में देना चाहिए, इस प्रकार का आदेश निकाला है, इससे बहुत सारे सांसदों को लाभ होगा। इसलिए मैं फिर से एक बार और आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, वह देशभर के लिए है और सभी सांसदों के लिए है। आने वाले दिनों में अगर महानगरों में किसी बात के लिए इंटरनल वॉर होगा, तो ट्रैफिक के लिए होगा,

ऐसा मेरा मानना है। यातायात, व्हीकल ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और महानगरों में डेवलपमेंट प्लान में जो रोड बताए गए हैं, वे फुल विड्थ में डेवलप नहीं हुए हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को सन् 2022 तक, जब हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, तब तक कुछ कामों को पूरा करने का उन्होंने तय किया है। मैं मानता हूँ कि अगर इस काम को भी वे हाथ में लेते हैं तो सभी महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, वे जागरूक होंगे और सभी रोड को फुल विड्थ में करने का प्रयास करेंगे।

मैं खास कर मुंबई शहर के बारे में बताऊँ तो महात्मा गांधी जी ने सन् 1942 में क्विट इंडिया का मूवमेंट प्रारंभ किया था। मुंबई शहर की विशेषता है कि पूरे देश भर का आकर्षण मुंबई शहर है, इसलिए मुंबई शहर में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई न कोई कहने वाला चाहिए। प्रधान मंत्री अगर इस बात को उठाते हैं तो मुंबई शहर की यह समस्या बहुत जल्दी और आसानी से दूर हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to raise the issue related to the recent unprecedented hike of airline fares from international airports in India, especially in my State of Kerala, to cash in on the demand for seats from non-resident Keralites returning to their work places in Gulf countries after Ramadan and other festivals.

Sir, the latest hike comes close on the heels of 200 to 400 per cent hike in the air fares during the summer vacation for educational institutions in the State. One-way fare from Trivandrum and other destinations to West Asia has suddenly gone up from the existing Rs. 6,000 to Rs. 12,000 range. The fare of

one-way economy class ticket from three international airports to the destinations of Gulf countries on April 1, the day after closing of the academic year for educational institutions, was in the range of Rs. 21,998 to Rs. 88,705.

Sir, this is a very important matter. The Civil Aviation Ministry should intervene in the matter immediately to reduce the air fares from Kerala to Gulf countries.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Speaker, Sir for giving me the opportunity to speak in Zero Hour. I am very glad that the hon. Minister of Railways, Piyushji is also here because this is a matter concerning him.

The issue that I want to raise today is the creation of a new Railway Zone in the State of Andhra Pradesh. The demand for the creation of new Railway Zone has been there for at least two decades. In the last term, you have also seen that I had raised this issue constantly. We have been trying to put pressure on the Central Government after its inclusion in the AP Reorganisation Act also. On February 27th of 2019, the hon. Railway Minister had made an important announcement that the Railway Zone would be granted. But the way we see it, Sir, it has been made in view of the Elections rather than keeping the sentiments of the people of Andhra in view. The Waltair Division, which is the most important division that needs to be there in the new Zone is totally omitted. It has a history of 125 years.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पिछले साढ़े तीन घंटे से लगातार बैठे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद

करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहां तीसरी बार आने का मौका दिया है। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो मैट्रो सिटी है, जो बड़ी सिटी है, टाउन है, वहां तो एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था है, लेकिन आज देश में बहुत सी ऐसी छोटी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, जहां अभी तक एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था नहीं है।

(1430/KN/GM)

आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्ट-अप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया हो। इसके माध्यम से आज देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो छोटा सिटी है, वहाँ भी एफएम रेडियो की व्यवस्था हो, जिससे विद्यार्थियों को, स्टूटेंट्स को, सभी को इस एफएम रेडियो की व्यवस्था मिल जाए। मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एफएम की व्यवस्था है, वहाँ कम वॉल्ट की बैटरी होने से पूरे टाउन को उसकी व्यवस्था नहीं मिल रही है। उसको भी पूरे वॉल्ट की बैटरी मिले। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र के हापुड़ जनपद में केन्द्र सरकार के कई विभाग हैं। वहाँ रेलवे, दिल्ली पुलिस, सेना, अर्ध सैनिक बल इत्यादि हजारों कर्मचारी निवास करते हैं या पूर्व कर्मचारी निवास करते हैं। लेकिन हापुड़ में कोई भी सीजीएचएस का चिकित्सालय नहीं है, जिसके कारण से इन परिवारों को अपनी चिकित्सा के लिए निजी अस्पताल में जाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इन परिवारजनों की सुविधा की दृष्टि से, केन्द्रीय सेवाओं में सेवारत इन कर्मचारियों की सुविधा की दृष्टि से एक सीजीएचएस चिकित्सालय हापुड़ के अन्दर खोले जाने की सरकार कृपा करें। मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। शायद यह रिकार्ड

हो जाएगा, क्योंकि आज जीरो अवर पहली बार लिया गया है, जिसमें आपने लगभग ढाई घंटे तक सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1431 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई)